इंद्रजीत

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

10 अगस्त, 1979

[वी. आर. कृष्णा अय्यर और पी. एन. शिंगल, जे.जे.]

वैधानिक मानकीकृत सजा-अनिवार्य लघु के साथ पूर्ण दायित्व अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन करने वाले मिलावटी भोजन की बिक्री के अपराधी के अपराध, चाहे वह संवैधानिक रूप से खराब हो, के लिए छह महीने की आर.आई. की सजा- खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, धारा 7 सपठित धारा 16, के नियमानुसार।

रिट याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 16 संवैधानिक रूप से वैध है। [257 जी]

नीति संसद के लिए है, संवैधानिकता न्यायालय के लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और हानिकारक व्यापार का विनियमन राज्य की पुलिस शक्ति के अंतर्गत आता है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जैसे कानून उसी शैली के हैं। [256 एफ-जी]

यदि कोई सजा, जैसा कि तत्काल अधिनियम में है, एक अनिवार्य न्यूनतम के रूप में निर्धारित की गई है और जो अनुच्छेद 21 के अनुरूप होने के लिए बहुत क्रूर है और अनुच्छेद 19 के तहत सही ढंग से उचित या सामाजिक रूप से बचाव योग्य होने के लिए बहुत यातनापूर्ण है, तो न्यायिक समीक्षा का मामला उत्पन्न हो सकता है। [256 जी-एच]

जज-प्रूफ सज़ा देना अपने आप में बुरा नहीं है। कभी-कभी सजा में न्यायिक उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से नरम पक्ष पर जहां सफेदपोश अपराधी शामिल होते हैं, भाग्य को बंधक बनाने में सामाजिक सुरक्षा देने से बचने के लिए, वाक्यों के विधायी मानकीकरण को प्रेरित करते हैं। न्यायालय के लिए अभी भी एक विस्तृत खेल बाकी है, और अनिवार्य न्यूनतम दंड संहिता के दिनों से परिचित हैं। [256 एच, 257 ए]

समान सुरक्षा के नुस्खे का भी उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि न्यायिक विवेक की सीमा के भीतर न्यायालय स्थापित सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक को वही प्रदान करता है जिसका वह हकदार है। [257 बी]

<u>टिप्पणी</u>

(ए) समाज की रक्षा के लिए विनियामक प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपे गए सार्वजनिक प्राधिकरण, उचित मामलों में, उन मुकदमों की जांच कर सकते हैं जो विनम्र लोगों के लिए उत्पीड़न हैं। भले ही वे तकनीकी रूप से कानून का उल्लंघन करते हों और समाज को केवल

न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हों और तय करें कि क्या उन्हें अपने अभियोजन की मंजूरी देनी चाहिए। [257 डी-ई]

(बी) विधायिका, अपने विवेक से, छोटे अपराधियों के लिए बने इन व्यापक जालों के माध्यम से बड़े अपराधी के बच निकलने के बिना सजा को कम करने के लिए कहीं न कहीं शक्ति देने की सलाह पर भी विचार कर सकती है। अन्यथा भी, कार्यपालिका के पास सजा कम करने की एक सामान्य शक्ति है और ऐसी शक्ति को सैद्धांतिक आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है, जब छोटे लोग कानून द्वारा पकड़े जाते हैं।

[257 ई-एफ]

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 449/1979 (संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

याचिकाकर्ता की ओर से आर.के. गर्ग और डी.के. गर्ग।

न्यायालय का आदेश कृष्णा अय्यर, जे. द्वारा दिया गया।

साहसी याचिकाकर्ता ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों को काल्पनिक रूप से चुनौती दी है। उनके आरोप का सार यह है कि उपरोक्त प्रावधान, एक साथ पढ़े जाने पर, मिलावटी भोजन की बिक्री के दोषी अपराधी को छह महीने की सश्रम कारावास की एक कठोर न्यूनतम

सजा देते हैं, इस प्रक्रिया में आरोपी के आपराधिक मनःस्थिति को साबित करने की आवश्यकता भी शामिल नहीं होती है। परिष्कृत रासायनिक परीक्षणों और जटिल सूत्रों पर निर्भर, अनिवार्य सजा के साथ यह पूर्ण दायित्व, छोटे भारतीय खुदरा व्यापार की अशिक्षित, कृषि संबंधी वास्तविकताओं में दमनकारी रूप से अनुचित है। ऐसा, एक वाक्य में, अधिवक्ता का तर्क है।

इस व्यापक तर्क का समर्थन करने वाले प्राथमिक सहारे पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। अधिवक्ता की शिकायत है कि सजा पर रोक लगाते समय हानिकारक प्रदूषकों और हानिरहित मिलावट करने वालों के बीच कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। न ही छोटे डीलरों और बड़े अपराधियों के बीच कोई बुद्धिमान अंतर है, और विक्रेताओं, बड़े और छोटे, को समान रूप से कठोर सजा के प्रोक्रस्टियन बिस्तर पर रखा जाता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 अधिवक्ता द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों को ख़त्म करने के लिए नियोजित संवैधानिक हथियार हैं।

सच कहूँ तो, हम संवैधानिकता के बारे में घबराहट से प्रभावित नहीं हैं, भले ही छोटे लोगों को प्रभावित करने वाले उत्पीड़न की संभावना वास्तविक हो और हमारी सहानुभूति का कारण हो। हम थोड़ी देर बाद कानून के विरुद्ध शिकायत पर एक क्षण के लिए विचार कर सकते हैं। सबसे पहले, हम असंवैधानिकता की बुराई को दूर करेंगे।

आइए बुनियादी बातों के बारे में स्पष्ट हों। नीति संसद के लिए है, संवैधानिकता न्यायालय के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और हानिकारक व्यापार का विनियमन राज्य की पुलिस शक्ति से संबंधित है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जैसे कानून उसी शैली के हैं।

यदि कोई सजा, जैसा कि यहां है, एक अनिवार्य न्यूनतम के रूप में निर्धारित की गई है और वह अनुच्छेद 21 के अनुरूप होने के लिए बहुत क्रूर है और अनुच्छेद 19 के तहत उचित रूप से उचित या सामाजिक रूप से बचाव योग्य होने के लिए बहुत यातनापूर्ण है तो न्यायिक समीक्षा का मामला उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हमें यहां कोई नहीं दिखता। न ही हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जज-प्रूफ़ सज़ा देना अपने आप में बुरा है। कभी-कभी सज़ा में न्यायिक उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से नरम पक्ष पर जहां सफेदपोश अपराधी शामिल होते हैं, भाग्य को बंधक बनाने में सामाजिक सुरक्षा देने से बचने के लिए, वाक्यों के विधायी मानकीकरण को प्रेरित करते हैं। अदालत के लिए अभी भी एक विस्तृत खेल बाकी है, और अनिवार्य न्यूनतम दंड संहिता (देखे- धारा 302) के दिनों से ही प्रचलित है। समान सुरक्षा के नियम का भी उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि न्यायिक विवेक की सीमा के भीतर अदालत स्थापित सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक को वही प्रदान करती है जिसका वह हकदार है।

श्री आर.के. गर्ग ने भावनापूर्वक आग्रह किया कि गरीबों और कमजोरों, जो खुदरा व्यापारियों का बड़ा, निचला क्षेत्र हैं, को मानकीकृत कारावास भुगतना होगा यदि खाद्य निरीक्षक उन्हें अदालत में चालान कर सकते हैं और, भोजन की रासायनिक संरचना में कुछ मामूली बदलाव पर बेचे गए, उन्हें बिना किसी कारण के केवल इसलिए दोषी ठहराया जाए क्योंकि, श्रृंखला के साथ, किसी बड़े व्यापारी ने उनसे घटिया वस्तुएं छीन ली हैं। हम इस बात से परेशान हैं कि यह संभव है कि जब कोई कार्यकारी नीति नहीं है जो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्गदर्शन करती है तो छोटे आदमी कठोर कानून का शिकार बन जाते हैं। छोटे-मोटे विजेता और बड़े शार्क अलग-अलग स्तर पर समाज पर काम करते हैं और लचीली नीति से कठोर समानता को नियंत्रित किया जाएगा।

यह संवैधानिकता में दंड नीति का मामला है और इसलिए यह एक तरह से न्यायिक सलाह की सीमा से बाहर है। फिर भी, हम यह कहने में बाध्य महसूस करते हैं कि समाज की रक्षा के लिए विनियामक प्रावधानों को लागू करने के लिए सौंपे गए सार्वजनिक प्राधिकरण, उचित मामलों में, उन अभियोजनों की जांच कर सकते हैं जो विनम्र लोगों के लिए उत्पीड़न हैं, भले ही वे तकनीकी रूप से कानून का उल्लंघन करते हों और समाज को केवल न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हों और निर्णय लें कि क्या उन्हें अपने अभियोजन की मंजूरी देनी चाहिए। विधायिका, अपने विवेक से, छोटे

अपराधियों के लिए बने इन व्यापक जालों के माध्यम से बड़े अपराधी को बच निकलने से बचाए रखने के लिए सजा को कम करने के लिए कहीं न कहीं शक्ति देने की सलाह पर भी विचार कर सकती है। अन्यथा भी, कार्यपालिका के पास सजा कम करने की एक सामान्य शक्ति है और जब छोटे लोग कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं तो ऐसी शक्ति को सैद्धांतिक आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

हम रिट याचिका को खारिज करते हैं क्योंकि इसमें कोई संवैधानिक अमान्यता नहीं बनाई गई है और जिन आधारों पर आग्रह किया गया है वे अधिक उचित रूप से संसद और कार्यपालिका के लिए अपील हैं।

वी.डी.के. याचिका खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक, राहुल कुमार** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।